

रायपुर. डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर स्थित एडवांस कॉर्डियक इंस्टीट्यूट के कॉर्डियोलॉजी विभाग के अत्याधुनिक कैथलैब में स्थापित रेडिएशन प्रोटेक्शन डिवाइस एगनेस्ट का उद्घाटन आज स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया. एचडीएफसी बैंक के सीएसआर गतिविधि परिवर्तन के अंतर्गत प्रदत्त यह रेडिएशन प्रोटेक्शन डिवाइस कैथलैब में कार्यरत डॉक्टर, नर्सिंग व पैरामेडिकल टीम की हानिकारक विकिरणों से रक्षा करेगा.

इस अवसर पर संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. विष्णु दत्त, अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय डॉ. तृप्ति नागरिया, अधीक्षक डॉ. एस. बी. एस. नेताम, कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. स्मित श्रीवास्तव, मनोरोग विभागाध्यक्ष डॉ. एम. के. साहू, सहायक अधीक्षक डॉ. डी. के. टंडन, प्रशासनिक अधिकारी रंजना ध्रुव, सीटीवीएस विभागाध्यक्ष डॉ. कृष्णकांत साहू समेत एचडीएफसी बैंक के अधिकारी मौजूद रहे.



विभागाध्यक्ष कॉर्डियोलॉजी विभाग डॉ. स्मित श्रीवास्तव ने रेडिएशन प्रोटेक्शन डिवाइस के संबंध में बताया कि एचडीएफसी बैंक के सीएसआर प्रभाग अरोह (एआरओएच) फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त यह प्रोटेक्शन सिस्टम कैथलैब में रेडिएशन के फैलाव एवं बिखराव को रोकता है. यह आधुनिक कैथलैब की एक अतिआवश्यक

सुरक्षा कवच में से एक है. कैथलैब में प्रतिदिन कार्डियक इंटरवेंशनल प्रक्रिया एक्स रे मशीन की सहायता से की जाती है (एक्स रे गाइडेड प्रोसीजर). पूरी टीम लम्बे समय तक यहां रहती है. ऐसे में पूरी टीम विकिरण के संपर्क में आती है. एगनेस्ट एक व्यापक, स्कैटर रेडिएशन (फैलने वाले विकिरण) सुरक्षा प्रणाली है, जो पूरी तरह से आधुनिक कैथ लैब में रेडिएशन के फैलाव एवं बिखराव को रोकने में मदद करती है. इसे सीआर्म एक्स रे मशीन की गति एवं दिशा के अनुसार इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह रोगी की दिशा के अनुसार सरलता से इधर उधर घूम सकता है. यह 91 % रेडिएशन से सुरक्षा देता है.

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट ने बहुत ही कम समय में एक नया आयाम स्थापित किया है. डॉ. स्मित श्रीवास्तव एवं उनकी टीम ने जिस जुनून के साथ एक लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को पूरा करने में मैं उनके साथ हूँ. आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भविष्य में चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर एवं अस्पताल के साथ - साथ एसीआई को विश्वस्तरीय संस्थान बनाने के लिए जो भी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं मानव संसाधन की ज़रूरत होगी, उसे शासन उपलब्ध करायेगी.